राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 184/2007

स्वर्गीय श्री नाथू लाल अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री झमकू लाल जी अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी-

1/1. अशोक अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू लाल जी अग्रवाल, उम्र लगभग 55 वर्ष;

1/2. गोपाल कृष्ण अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू लाल जी अग्रवाल, उम्र लगभग 52 वर्ष;

1/3. कुमारी ललिता पुत्री स्वर्गीय श्री नाथू लाल जी अग्रवाल, उम्र लगभग 45 वर्ष;

सभी निवासी उपरलापाड़ा, गांधी चौक, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. कृषि उपज मंडी समिति, चित्तौड़गढ़।

3. भूमि अधिग्रहण अधिकारी (उपखंड अधिकारी), चित्तौड़गढ़।

----प्रतिवादीगण

संलग्न

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 469/2007

इंदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, चित्तौड़गढ़

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. कृषि उपज मंडी समिति, चित्तौड़गढ़।

3. भूमि अधिग्रहण अधिकारी (उपखंड अधिकारी), चित्तौड़गढ़।

----प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री एम.एस. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनीत दवे श्री त्रिभुवन गुप्ता
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री आई.आर. चौधरी, एएजी, श्री पवन भारती द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सहायता प्राप्त

माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्रशेखर

माननीय श्री न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर

आदेश

23/09/2024

(प्रति माननीय श्री चंद्रशेखर, जे):

ये विशेष अपीलें नाथू लाल अग्रवाल द्वारा दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1932/1990 तथा इंद्र गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ द्वारा दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1938/1990 में पारित रिट न्यायालय के 2 जनवरी 2007 के सामान्य आदेश के विरुद्ध हैं।

2. इंद्र गृह निर्माण सहकारी समिति एक गृह निर्माण सहकारी समिति (संक्षेप में सहकारी समिति) है जो 30 अप्रैल 1982 को पंजीकृत हुई थी, जिसने दावा किया था कि उसने खसरा संख्या 191/2 में नाथू लाल अग्रवाल से भूमि का एक टुकड़ा खरीदा था, जो पंजीकृत खातेदार था और बाद में उक्त भूमि के टुकड़े की आराजी संख्या बदलकर 414 कर दी गई थी। सहकारी समिति का दावा है कि उसने खसरा संख्या 191/3 में एक और भूमि खरीदी थी और इस भूमि के टुकड़े की आराजी संख्या भी बदलकर 415 कर दी गई थी। अपीलकर्ता-नाथू लाल अग्रवाल ने दावा किया कि वह चित्तौड़गढ़ तहसील और जिले के अंतर्गत सेंती गांव में नए खसरा संख्या 3019, 3020, 3021, 3022, 392 और 393 के अंतर्गत आने वाली भूमि का भूमिधारक था। अपीलार्थी-नाथू लाल अग्रवाल की मृत्यु पर, उनके कानूनी वारिसों और उत्तराधिकारियों अर्थात् अशोक अग्रवाल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और सुश्री ललिता को वर्तमान कार्यवाही में पारित 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

3. ये अपीलकर्ता भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जारी 21 दिसंबर 1988 की अधिसूचना और धारा 6 और 17 के तहत जारी 16 मार्च

1990 की घोषणा को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिकाओं के खारिज होने से व्यथित हैं।

4. चूंकि इन विशेष अपीलों में मुख्य तर्क श्री एम.एस. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो विशेष अपील संख्या 184/2007 में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील हैं, हम उस विशेष अपील में दिए गए तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान देंगे।

5. संक्षेप में कहा जाए तो, 29 जनवरी 1981 को राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें नए मंडी यार्ड के निर्माण के लिए 'ए' श्रेणी की 50 से 80 एकड़, 'बी' श्रेणी की 40 से 60 एकड़, 'सी' श्रेणी की 20 से 40 एकड़ और 'सबयार्ड' के लिए 10 से 20 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की बात कही गई थी। इसके बाद, 5 नवंबर 1981 को राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत एक घोषणा जारी की गई और दोनों को अपीलकर्ता-नाथू लाल अग्रवाल ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 700/1982 दायर करके चुनौती दी। इस बीच, कृषि उपज मंडी समिति (संक्षेप में समिति) और नाथू लाल अग्रवाल के बीच समझौता हो गया और उक्त अधिसूचना/घोषणा के तहत विषयगत भूमि का एक हिस्सा उनके पक्ष में जारी कर दिया गया। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 20 दिसंबर 1985 को अवार्ड जारी किया और शेष भूमि के लिए उन्हें मुआवजा दिया गया। हालांकि, 21 अगस्त 1986 को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से उक्त अवार्ड को फिर से खोलने की मांग की गई। इससे व्यथित होकर, नाथू लाल अग्रवाल ने सिविल मूल मामला संख्या 190/86 शीर्षक "नाथूलाल बनाम राज्य" में मुंसिफ, चित्तौड़गढ़ की अदालत से स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। उक्त कार्यवाही में समिति ने एक आवेदन दायर किया जिसमें यह वचन दिया गया कि वह 21 अगस्त 1986 के नोटिस के अनुसार आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगी। अंततः 22 दिसंबर 1988 को सिविल मूल मामला संख्या 190/86 में निर्णय सुनाया गया तथा 20 दिसंबर 1985 का निर्णय अंतिम हो गया तथा पक्षों के बीच समझौते की शर्तें स्वीकृत हो गईं।

6. हालांकि, धारा 17 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए दूसरी कार्यवाही राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 4 के तहत 6 अक्टूबर 1988 की अधिसूचना के साथ की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था और राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 21 दिसंबर 1988 को एक और नोटिस जारी किया गया था, जिसमें नाथू लाल अग्रवाल के पक्ष में जारी की गई भूमि का कुछ हिस्सा भी शामिल था; यह 6 अप्रैल 1989 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि अधिसूचना 3 मई 1989 को

स्थानीय समाचार पत्र 'मेवाड़ी मीरा' में ही प्रकाशित हुई थी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 28 अगस्त 1989 को एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। फिर भी, धारा 17(1) और (4) के साथ धारा 6 के तहत घोषणा 16 मार्च 1990 को जारी की गई थी। इसलिए, 21 दिसंबर 1988 की अधिसूचना और 16 मार्च 1990 की घोषणा को अपीलकर्ताओं द्वारा रिट कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया है।

7. रिट न्यायालय ने पूर्व अधिग्रहण कार्यवाही तथा नाथू लाल अग्रवाल के साथ हुए समझौते, जिसके अनुसार अधिग्रहण की जा रही भूमि का एक भाग उनके पक्ष में छोड़ा गया था, का संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए रुख की जांच की तथा निम्नलिखित तरीके से अपना मत प्रस्तुत किया:-

> ".....प्रतिवादियों ने अपने उत्तर में कहा है कि विचाराधीन भूमि अधिग्रहित की गई है, क्योंकि यह कृषि उपज मंडी की सीमा में स्थित है, जो पूर्व में अधिग्रहित भूमि पर स्थापित की गई है। वर्तमान भूमि, जो 1894 के अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना का विषय है, के संबंध में 21.12.88 को एक समग्र अधिसूचना जारी की गई थी। प्रतिवादियों ने कहा है कि पूर्व में दायर किए गए समझौते पर कृषि उपज मंडी के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं थे, क्योंकि भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी थी तथा सचिव के पास समझौता करने का कोई अधिकार नहीं था।
>
> याचिका की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.06 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत अभिलेखों की जांच करने का प्रस्ताव किया गया था। अभिलेखों को बुलाया गया और उनकी जांच की गई। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अब जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, वह उस क्षेत्र में स्थित है जिसे पहले अधिग्रहित किया गया था और राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया था कि यदि क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं किया जाता है तो क्षेत्र के मालिक मंडी यार्ड से गुजरेंगे और इससे अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा और अनावश्यक रूप से कृषि उपज मंडी के कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी। प्रकाशन आदि के आधारों पर गंभीरता से जोर नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने गंभीरता से तर्क दिया कि एक बार समझौता हो जाने के बाद कोई कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम कृष्ण लाल अरनेजा और अन्य (2004) 8 एससीसी 453) और यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मुकेश हंस (2004) 8 एससीसी 14) पर भरोसा किया। उनका मुख्य तर्क यह है कि धारा 17 की घोषणा क्यों की गई, इसका कोई कारण नहीं है क्योंकि कोई तात्कालिकता नहीं थी। तात्कालिकता और 1984 के अधिनियम की धारा 5ए के तहत जांच से बचने के लिए कोई निश्चित कारण होना चाहिए। यह केवल बहस करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिपक्ष आग्रह किया कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस मामले पर भरोसा किया गया है, वह तथ्यों के आधार पर भिन्न है। एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पहले की कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं 1894 के अधिनियम की धारा 17 की घोषणा की वैधता पर सवाल उठाया था और इसलिए, अत्यावश्यकता खंड को बनाए नहीं रखा गया था और दूसरे मामले में भूमि पर कब्जे के लिए कार्यवाही 'फूलवालों की सैर' नामक त्यौहार के लिए आवश्यक थी, जिसे न्यायालय के अनुसार भूमि अधिग्रहण किए बिना भी बिना किसी बाधा के मनाया जा रहा था और इसलिए, भूमि अधिग्रहण किए बिना भी उद्देश्य पूरा हो गया और इस प्रकार अत्यावश्यकता खंड को उचित नहीं माना गया और इसलिए भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया कि अब जिस भूमि को अधिग्रहित करने की मांग की जा रही है, वह मंडी यार्ड के भीतर स्थित है और किसी निजी मालिक को इस यार्ड से गुजरने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मंडी यार्ड ने काम करना शुरू कर दिया है और मंडी यार्ड को बनाए रखने के लिए भूमि की आवश्यकता है।

मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अपने विचार व्यक्त किए हैं।

जहां तक 1984 के अधिनियम की धारा 17 के प्रश्न का संबंध है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिन दो मामलों पर भरोसा किया

गया है, वे अलग-अलग हैं। वे इस बात को सामान्य नियम के रूप में नहीं मानते हैं कि संतुष्टि पर रिट क्षेत्राधिकार में सवाल उठाया जा सकता है। बल्कि कृष्ण लाल के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून राज्य सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिन दो मामलों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं। अत्यावश्यकता खंड राज्य सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित है, इसलिए दी गई परिस्थितियों में इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यदि दी गई परिस्थितियों में राज्य ने माना है कि उसे इसकी आवश्यकता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कुछ गड़बड़ है।

इस मामले को देखते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। इस मामले को देखते हुए याचिका में कोई दम नहीं है, इसे खारिज किया जाता है।

8. विशेष अपील संख्या 184/2007 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम.एस. सिंघवी ने अनेक तर्क दिए हैं जैसे (i) रिट कोर्ट ने मामले के आधारभूत तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि प्रतिवादियों द्वारा विषयगत भूमि पर कब्जा लेने के संबंध में कोई निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित नहीं किया गया कि पुरस्कार विजेताओं को मुआवजा दिया गया था; (ii) रिट कोर्ट ने केवल "यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम कृष्ण लाल अरनेजा एवं अन्य" (2004) 8 एससीसी 453 में दिए गए निर्णय का हवाला देकर धारा 6 और 17 के तहत जारी अधिसूचना को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया; (iii) रिट न्यायालय ने इस स्वीकृत स्थिति को नजरअंदाज कर दिया कि धारा 4 के तहत अधिसूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की गई थी और धारा 6 के तहत घोषणा 21 दिसंबर 1988 को धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के 15 महीने बाद जारी की गई थी; और (iv) रिट न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई इस दलील पर फैसला नहीं सुनाया कि 12 दिसंबर 1988 को जारी की गई अधिसूचना शक्ति का एक रंग-रूपी प्रयोग थी।

9. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1870 (1870 का अधिनियम X) को प्रतिस्थापित किया। एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाने के उद्देश्यों और कारणों का कथन यह दर्शाता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1870 में संशोधन भारत सरकार द्वारा कई वर्षों से

विचाराधीन था, विशेष रूप से स्थानीय सरकारों के साथ संचार के मद्देनजर। 1870 के अधिनियम X को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा परिषद में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1870 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह संविधान-पूर्व कानून था जो भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या सार्वजनिक हित के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रभावी नहीं पाया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में न केवल केंद्र सरकार द्वारा बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी कई संशोधन किए गए। इसलिए, पुनर्वास और पुनर्स्थापन मुद्दों को विकास प्रक्रिया के लिए अंतर्निहित के रूप में मान्यता देने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया जो 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ; 27 सितंबर 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

10. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 में प्रावधान है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए यदि किसी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है तो उपयुक्त सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी। धारा 4 की अधिसूचना उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जानी आवश्यक है, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। धारा 4 में यह भी प्रावधान है कि कलेक्टर उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना देगा। चूंकि समुचित सरकार का उद्देश्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की संपत्ति का अधिग्रहण करना है, धारा 5-ए धारा 4 के तहत अधिसूचित किसी भी भूमि में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति उठाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। धारा 5-ए की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि कलेक्टर आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति या वकील द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे, या तो धारा 4 (1) के तहत अधिसूचित भूमि के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा या ऐसी भूमि के विभिन्न भागों के संबंध में अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करेगा, जो समुचित सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। उप-धारा (4) आगे स्पष्ट करती है कि वह व्यक्ति भूमि में रुचि रखने वाला माना जाएगा जो मुआवजे में रुचि का दावा करने का हकदार होगा। जबकि धारा 4 में समुचित सरकार द्वारा भूमि का एक टुकड़ा अधिग्रहित करने का मात्र इरादा दर्शाया गया है, धारा 6 में यह प्रावधान है कि यदि समुचित सरकार धारा 5-ए की उपधारा (2) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह संतुष्टि प्राप्त

करती है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य अथवा कंपनी के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता है, तो वह सरकार के सचिव अथवा उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से इस आशय की घोषणा करेगी तथा समय-समय पर विभिन्न घोषणाएं की जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 6 के अंतर्गत घोषणा को उसके अंतर्गत प्रदत्त कुछ विधिक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जैसे कि प्रत्येक घोषणा को सरकारी राजपत्र में तथा उस क्षेत्र में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें भूमि स्थित है, जिनमें से कम से कम एक समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में होगा। यह उल्लेख करना सर्वथा प्रासंगिक है कि धारा 6 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के अंतर्गत कोई भी घोषणा इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगी कि भूमि सार्वजनिक उद्देश्य या कंपनी के लिए आवश्यक है और इसलिए ऐसी घोषणा करने के लिए धारा 6 के अंतर्गत वैध घोषणा की शर्तें पूरी होनी चाहिए। हमारी राय में, उपयुक्त सरकार या उसकी ओर से यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि त्रुटि या भूल पर्याप्त प्रकृति की नहीं थी, बल्कि केवल तकनीकी त्रुटि या भूल थी। हितबद्ध व्यक्ति का यह मूल अधिकार कि प्रश्नगत अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है और सार्वजनिक उद्देश्य को विशेष रूप से हितबद्ध व्यक्ति के ध्यान में लाया गया था, इस आधार पर टाला नहीं जा सकता कि क्षेत्र में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना और धारा 6 के अंतर्गत घोषणा प्रकाशित न करना एक साधारण भूल थी या हितबद्ध व्यक्ति को प्रस्तावित अधिग्रहण के बारे में जानकारी थी।

11. यह अभिलेख में दर्ज है और तहसीलदार की दिनांक 28 अगस्त 1989 की रिपोर्ट से भी यह स्थापित होता है कि दिनांक 21 दिसंबर 1988 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना केवल स्थानीय समाचार पत्र मेवाड़ी मीरा में प्रकाशित हुई थी। “मुंशी सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य” (1973) 2 एससीसी 337 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक उद्देश्य की सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है और अधिग्रहण की अधिसूचना का अभिन्न अंग है। धारा 4 और धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान का अनुपालन न करने का प्रभाव, जिसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में प्रसारित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की आवश्यकता होती है, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, यह होगा कि प्रभावित पक्षों को उपयुक्त सरकार द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण करने के इरादे के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। वास्तव में, यह प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता है कि प्रभावित पक्षों को यह बताया जाए कि उपयुक्त सरकार उनकी संपत्ति अधिग्रहण करने का इरादा रखती है। वर्तमान मामले में, कानून में यह आवश्यकता पूरी

ताकत के साथ लागू होगी क्योंकि कोई विशेष कानून या विनियमन या कोई प्रथागत प्रथा इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई गई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि प्रभावित पक्षों को धारा 4 के तहत अधिसूचना और धारा 17 के साथ धारा 6 के तहत घोषणा के बारे में जानकारी थी। हालांकि, प्रस्तावित अधिग्रहण कार्यवाही में इस घातक कमी को रिट कोर्ट द्वारा संबोधित नहीं किया गया था।

12. अत्यावश्यकता खंड का आह्वान भी कानून में गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण था और किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं था। नई मंडी यार्ड की स्थापना के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपीलकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण आवश्यक नहीं था। वास्तव में, एक नई मंडी यार्ड की स्थापना की गई है और अपीलकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए प्रतिवादियों ने दलील दी कि अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को नई मंडी यार्ड से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। "नारायण गोविंद गवटे बनाम महाराष्ट्र राज्य" (1977) एससीसी 133 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि धारा 17(4) के तहत प्रावधानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) और 5-ए से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि संबंधित प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या इस तरह की अत्यावश्यकता है कि धारा 5-ए के तहत सारांश कार्यवाही भी समाप्त कर दी जानी चाहिए। इसलिए, यह केवल तात्कालिकता का अस्तित्व नहीं है, बल्कि धारा 5-ए के तहत जांच से बचने की आवश्यकता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। "पंजाब राज्य बनाम गुरदयाल सिंह" 1980 2 एससीसी 471 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को जबरन लेना एक गंभीर मामला है और वास्तविक तात्कालिकता को छोड़कर, जहां सार्वजनिक हित सुनवाई के लिए आवश्यक न्यूनतम समय भी बर्दाश्त नहीं करता है, भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत जांच को बाधित नहीं करना चाहिए।

13. एक अन्य निर्णय में, "आनंद सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" (2010) 11 एससीसी 242 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना:

> "43. धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करने की असाधारण और असाधारण शक्ति, ऐसे मामले में जहां भूमि पर कब्जा तत्काल आवश्यक है या अप्रत्याशित आपात स्थिति में अधिनियम की धारा 17 में प्रदान की गई है। ऐसी शक्ति एक नियमित शक्ति नहीं है और तत्काल कब्जे की आवश्यकता वाली परिस्थितियों को छोड़कर इसे

हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करने में असाधारण शक्ति के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश धारा 17 में ही दिए गए हैं। शक्ति जितनी असाधारण होगी, सरकार को इसके प्रयोग में उतनी ही अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए, सरकार को स्पष्ट रूप से धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करने से पहले इस पहलू पर अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या तात्कालिकता ऐसी प्रकृति की है जो धारा 5-ए के तहत संक्षिप्त जांच को समाप्त करने का औचित्य साबित करती है।

44. अधिसूचना में वैधानिक वाक्यांश की पुनरावृत्ति कि राज्य सरकार संतुष्ट है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि की तत्काल आवश्यकता है और प्रावधान में निहित है धारा 5-ए में यह प्रावधान लागू नहीं होगा, हालांकि सरकार के पक्ष में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्वापेक्षित शर्तें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी धारणा परिस्थितियों के कारण खारिज हो सकती है जिनका उस उद्देश्य से कोई उचित संबंध नहीं है जिसके लिए शक्ति का प्रयोग किया गया है। धारा 17 के तहत शक्ति के प्रयोग को चुनौती दिए जाने पर सरकार को न्यायालय के समक्ष उचित सामग्री प्रस्तुत करनी होगी कि धारा 5-ए के तहत जांच से छूट देने की राय सरकार द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर उचित विचार करने के बाद बनाई गई है।

45. यह सही है कि धारा 17 के तहत सरकार को दी गई शक्ति प्रशासनिक है और उसकी राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे मामले में जहां राय उद्देश्य से संबंधित नहीं विचारों के आधार पर तात्कालिकता के बारे में बनाई गई है, ऐसे प्रशासनिक निर्णय की न्यायिक समीक्षा आवश्यक हो सकती है।

46. किन परिस्थितियों में आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह धारा 17(2) में निर्दिष्ट है, लेकिन धारा 17(1) के तहत तात्कालिकता के इस्तेमाल की आवश्यकता वाली परिस्थितियों का प्रावधान में उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र (आवासीय उद्देश्यों के लिए) या शहर के नियोजित विकास के लिए कई साल या दशकों का समय लगता है और इसलिए, कोई कारण नहीं है कि धारा 5-ए के तहत परिकल्पित सारांश जांच न की जाए

और भूस्वामियों/हितधारक व्यक्तियों की आपत्तियों पर विचार न किया जाए। कई मामलों में, सामान्य धारणा के आधार पर धारा 5-ए के तहत जांच पूरी होने में संभावित देरी को जांच से छूट देने में असाधारण शक्ति के आह्वान का कारण बना दिया जाता है, जबकि यह एहसास नहीं होता कि भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार को छीन लिया गया है और कुछ प्रयास से हमेशा पूरा किया जा सकता है, लेकिन जांच में तेजी लाई जा रही है।

47. धारा 17 में विशेष प्रावधान किया गया है ताकि योग्य और वास्तविक तात्कालिकता के मामलों में धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त किया जा सके। सरकार को इस पहलू पर अपना दिमाग लगाना होगा कि तात्कालिकता ऐसी प्रकृति की है कि धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करना आवश्यक है। हमने पहले ही इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर गौर किया है। इस न्यायालय के दो निर्णयों अर्थात् नारायण गोविंद गवटे और पिस्ता देवी में विचारों का टकराव है। ओम प्रकाश 13 में इस न्यायालय ने माना कि पिस्ता देवी में निर्णय उस समय की तथ्यात्मक स्थिति तक ही सीमित होना चाहिए जब इसे सुनाया गया था और दो न्यायाधीशों की पीठ नारायण गोविंद गवटे में निर्णय के विपरीत प्रस्ताव नहीं रख सकती थी। हम सहमत हैं।

48. इस मुद्दे के संबंध में कि क्या अधिसूचना से पहले और अधिसूचना के बाद की देरी से अत्यावश्यकता शक्ति का आह्वान शून्य हो जाएगा, फिर से मामला कानून सुसंगत नहीं है। इस पहलू पर इस न्यायालय का दृष्टिकोण उन मामलों में अलग-अलग तथ्यात्मक स्थिति के कारण भिन्न है। हमारी राय में इस तरह की देरी का अत्यावश्यकता शक्ति के आह्वान के प्रश्न पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, खासकर ऐसी स्थिति में जहां उपयुक्त सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई है जो यह उचित ठहराए कि अत्यावश्यकता ऐसी प्रकृति की थी जिसके लिए धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करना आवश्यक था।

14. रिट कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 17 के तहत संतुष्टि पर रिट कोर्ट द्वारा विचार किया जा सकता है, यह देखते हुए कि “यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स बनाम कृष्ण लाल अरनेजा एंड ऑर्स” (2004) 8 एससीसी 453 और

“यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स बनाम मुकेश हंस” (2004) 8 एससीसी 14 के फैसले यह नहीं मानते कि संतुष्टि पर रिट क्षेत्राधिकार में सवाल उठाया जा सकता है। यह एक सुस्थापित कानून है कि धारा 17(4) के तहत संतुष्टि प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि है और रिट कोर्ट सरकार के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक यह प्रदर्शित नहीं हो जाता कि सरकार के पास ऐसी सामग्री थी जिसके आधार पर वह निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रूप से अपनी संतुष्टि बना सकती थी। हालांकि, यह भी तय है कि यदि वे सामग्री जिसके आधार पर उपयुक्त सरकार ने अपनी राय बनाई या संतुष्टि प्राप्त की, इतनी अपर्याप्त थी कि कोई भी व्यक्ति उस निष्कर्ष पर यथोचित रूप से नहीं पहुंच सकता था, तो न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। “मुंशी सिंह” मामले में अधिग्रहण की कार्यवाही इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि “क्षेत्र का नियोजित विकास” किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई विचार व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त था। “मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड बनाम मोहम्मद शफी और अन्य” (1992) 2 एससीसी 168 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही रद्द कर दी कि “आवासीय” के रूप में उल्लिखित सार्वजनिक उद्देश्य अस्पष्ट था। हम इन निर्णयों का उल्लेख इस विषय पर कानून को दोहराने के लिए भी कर रहे हैं कि धारा 17 के तहत अधिग्रहण के लिए सरकार द्वारा बताए गए कारण को धारा 4 और धारा 6 के तहत अपेक्षित रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। “हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डेरियस शापुर चेनाई और अन्य” (2005) 7 एससीसी 627 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य अपनी "प्रमुख डोमेन" की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो रिट कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। "हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना:-

> “...8. अधिनियम की धारा 6 में निहित निष्कर्षात्मकता निर्विवाद रूप से आवश्यकता और उद्देश्य से जुड़ी हुई है और इस संबंध में सामान्यतः न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जब किसी कानून द्वारा सुनवाई का अवसर स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, तो उसका पूरी ईमानदारी से अनुपालन किया जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 4 5-ए और 6 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे मामले में

न्यायालय, जहां अधिनियम की धारा 5-ए के प्रावधानों का पूर्ण गैर-अनुपालन या पर्याप्त गैर-अनुपालन हुआ है, अपने हाथ जोड़कर रिट याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) एक घोषणा को एक निर्णायक साक्ष्य बनाती है। लेकिन जब निर्णय लेने की प्रक्रिया ही प्रश्न में हो, तो न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यदि आदेश आक्षेपित मामला अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता जैसे सुप्रसिद्ध सिद्धांतों से ग्रस्त है। इसके अलावा, जब 3 वैधानिक प्राधिकरण इतनी बड़ी शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाना चाहिए।

9. यह सामान्य बात है कि किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सुनवाई एक प्रभावी सुनवाई होनी चाहिए, न कि केवल औपचारिकता। सार्वजनिक उद्देश्य और उसकी उपयुक्तता के संबंध में राय बनाने से पहले प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए और अप्रासंगिक कारकों को अस्वीकार करना चाहिए। राज्य को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में कानून में कोई गलत दिशा नहीं अपनानी चाहिए। यह भी विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा 5-ए एक मूल्यवान महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है और संविधान के अनुच्छेद 300-ए में निहित प्रावधानों के संबंध में इसे मौलिक अधिकार के समान माना गया है..."

15. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 4 (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 29 जनवरी 1981 के अंतर्गत नाथू लाल अग्रवाल की भूमि अधिग्रहित की जानी थी। यह भी अभिलेख में है कि नाथू लाल अग्रवाल और प्रतिवादी संख्या 3 के मध्य समझौता हुआ था और आराजी संख्या 1747/1 का, 1743/1, 1746, 1748, 1742/1 खा और 1743/2 के अंतर्गत भूमि उनके पक्ष में अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई थी। वर्तमान विवाद की उत्पत्ति भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 1990 से हुई है। इस अधिसूचना के अंतर्गत श्रीमती कमल देवी, श्रीमती मनोहरी देवी और भवरलाल गोवर्धनलाल के अलावा, खसरा संख्या 3020, 3021, 3022, 414 और 413 में फैली लगभग 1.80 हेक्टेयर भूमि भी इसमें शामिल है। हालांकि, प्रतिवादियों ने यह मामला उठाया है कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 19 सितंबर 2005 को विषयगत भूमि पर कब्जा कर लिया और

समिति को सौंप दिया। उन्होंने 20 सितंबर 2005 के एक संचार पर भरोसा किया है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ के तहसीलदार ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी को सूचित किया कि विषयगत भूमि का कब्जा समिति के सचिव को दिया गया था। समिति ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज म्यूटेशन प्रविष्टियों के आधार पर यह दलील भी दी कि विषयगत भूमि का कब्जा भूमि धारकों से लिया गया था और उसे सौंप दिया गया था। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों के इस रुख पर गंभीरता से विवाद किया, क्योंकि विषयगत भूमि पर कब्जा लेने और कब्जा सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। वास्तव में, प्रतिवादियों द्वारा संवत 2068-2071 के लिए खसरा संख्या 3019 के संबंध में प्रस्तुत जमाबंदी से पता चलता है कि समिति के नाम पर राजस्व अभिलेखों में केवल 0.88 हेक्टेयर भूमि दर्ज की गई थी। हम आगे पाते हैं कि नाथू लाल अग्रवाल ने यह रुख अपनाया कि उनके पास खसरा संख्या 3019 में 0.10 हेक्टेयर भूमि है और वे उक्त संपत्ति पर खेती कर रहे हैं। खसरा संख्या 3020 और 3021 के संबंध में, नाथू लाल अग्रवाल ने निर्बाध भौतिक और खेती कब्जे की दलील दी। उन्होंने गूगल अर्थ से जियो मैपिंग सैटेलाइट चित्र भी प्रस्तुत किए, जिसमें पूरे क्षेत्र को हरा-भरा दिखाया गया। यह भी पता चला है कि खसरा संख्या 3022 पर दो कमरे बनाए गए थे और वहां एक पानी का कुआं भी था। नाथू लाल अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारियों ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वहां एक विद्युत मीटर लगाए जाने का भी सबूत पेश किया है। यह भी साबित किया गया है कि 20 दिसंबर 1985 के समझौते में खसरा संख्या 392 के अंतर्गत आने वाली लगभग 0.17 हेक्टेयर भूमि और खसरा संख्या 393 के अंतर्गत आने वाली लगभग 0.19 हेक्टेयर भूमि नाथू लाल अग्रवाल के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि यही कारण था कि खसरा संख्या 392 और 393 के अंतर्गत आने वाली भूमि का केवल एक हिस्सा समिति के नाम पर म्यूटेशन किया गया था।

16. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच करने के पश्चात, हम पाते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा लिया गया यह रुख कि अपीलकर्ताओं का विषयगत संपत्ति के एक हिस्से पर कब्जा अतिक्रमण की प्रकृति का था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि प्रतिवादी संपूर्ण विषयगत संपत्ति पर अपना कब्जा साबित नहीं कर सके और यहां तक कि म्यूटेशन प्रविष्टियों में भी विषयगत संपत्ति के केवल एक हिस्से का उल्लेख है, इसलिए अपीलकर्ताओं को अतिक्रमणकारी नहीं कहा जा सकता। 22 दिसंबर 1988 की समझौता डिक्री अंतिम हो गई है और इसलिए 5 नवंबर 1981 की घोषणा के तहत भूमि का एक हिस्सा, जिसे नाथू लाल अग्रवाल के पक्ष में छोड़ा गया था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत पुनः

अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है; ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री के आधार पर भूमि की रिहाई अंतिम हो गई है। इसके अलावा, म्यूटेशन प्रविष्टियाँ राजस्व एकत्र करने के लिए की जाती हैं और म्यूटेशन प्रविष्टियों से जो सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में म्यूटेशन का आदेश दिया गया है, उसे कब्जा माना जाएगा। लेकिन फिर, खसरा संख्या 392 और 393 के तहत संपत्ति के हिस्से के संबंध में म्यूटेशन प्रविष्टियाँ सिविल मूल मामला संख्या 190/1986 में निर्णय और डिक्री के सामने आदेशित नहीं की जा सकती थीं।

17. अपीलकर्ताओं ने उन्हें मुआवजे के भुगतान पर विवाद किया है। इस संदर्भ में, हम देख सकते हैं कि भूमि-धारकों के नाम पर चेक तैयार करना यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं था कि भूमि-धारकों को मुआवजा दिया गया था। मुआवजे की राशि के लिए चेक तैयार करना प्रतिवादियों के कार्यालय की सीमाओं के भीतर रहा है और यह न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया है कि अपीलकर्ताओं को मुआवजा दिया गया था। "पंजाब राज्य बनाम अमर सिंह हरिका" एआईआर 1966 एससी 1313 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या किसी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्णय लेने या अपने अधिकार और शक्ति के भीतर कार्य करने का आदेश अवैध होगा यदि संबंधित अधिकारी को पहले ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बर्खास्तगी का आदेश केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब इसे संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाए या अन्यथा प्रकाशित किया जाए।

18. उपर्युक्त कारणों से, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1932/1990 और 1938/1990 में पारित दिनांक 02 जनवरी 2007 के आदेश को अपास्त किया जाता है और फलस्वरूप डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 184/2007 और 469/2007 को स्वीकार किया जाता है। हालांकि, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि प्रस्तावित अधिग्रहण के तहत भूमि के उन हिस्सों को छोड़कर, जिन्हें नाथू लाल अग्रवाल के पक्ष में छोड़ा गया था, प्रतिवादी-राजस्थान राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एक नई कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।

(कुलदीप माथुर),जे **(श्री चंद्रशेखर),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।